केंद्रीय योजनाओं और तकनीकी संस्थाओं से भी कौशल विकास प्रशिक्षण को जोड़ें : योगी

सीएम ने देखी उद्यमिता विकास प्रशिक्षण व टूलकिट वितरण के संबंध में प्रस्तुतीकरण

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनपद, एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के तहत दक्षता, कौशल विकास, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण के कार्यक्रमों को केंद्रीय योजनाओं व तकनीकी संस्थाओं से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे ओडीओपी से जुड़े लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही लाभार्थियों की दक्षता, कौशल व उद्यमिता विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। सीएम ने ये निर्देश बुधवार को ओडीओपी कार्यक्रम के अंतर्गत दक्षता, कौशल विकास व उद्यमिता विकास प्रशिक्षण व टूलकिट वितरण योजना के संबंध में प्रजेंटेशन देखने के बाद दिए हैं।

उन्होंने कहा कि 'आत्मनिर्भर भारत' की परिकल्पना को साकार करने के लिए ओडीओपी के तहत परंपरागत उद्योग और क्षेत्र विशेष के उत्पादों को प्रोत्साहित करने से 'वोकल फॉर लोकल' के अभियान को बल मिलेगा। उन्होंने ओडीओपी योजना के प्रति कारीगर, हस्तशिल्पियों व उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के भी निर्देश दिए हैं।

कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिल एमएसएमई नवनीत सहगल ने सीएम को बताया कि ओडीओपी योजना के तहत अब तक 41 हजार 472 हस्तशिल्पियों व उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। वहीं 39 हजार 73 टूलकिट वितरित किए जा चुके हैं। इस मौके पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त संजीव कुमार मित्तल, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार समेत अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

भविष्य में आसपास बनें आवासीय व गैरआवासीय भवन : मुख्यमंत्री

सीएम ने किया 13 जिलों में बने राजस्व विभाग के 18 भवनों का लोकार्पण

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को 13 जिलों में राजस्व विभाग के 118 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 18 भवनों का लोकार्पण किया। इनमें आवासीय व गैरआवासीय दोनों तरह के भवन शामिल हैं। इस मौके पर सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये विभिन्न जिलों में मौजूद पुराने सरकारी भवनों की स्थिति की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा, भविष्य में आवासीय व गैरआवासीय भवन आपपास ही हों।

जिससे इन गैरआवासीय भवनों में अधिकांश विभागों के कार्यालय स्थापित किए जा सकें। सीएम ने कहा कि विभिन्न जिलों में बने गैरआवासीय भवनों में सरकारी कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। इससे जनता के काम सुगमता से हो सकेंगे। वहीं, आवासीय भवनों को सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को आवंटित किया जाएगा। इससे जहां इन लोगों की आवासीय समस्या का समाधान होगा, वहीं उन्हें कार्यालय आने-जाने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। इससे अधिकारी व कर्मचारी कार्यालय में अधिक समय देकर जनसमस्याओं का निराकरण प्रभावी ढंग से कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता की समस्याओं के प्रभावी ढंग से निराकरण के लिए कटिबद्ध है। कार्यक्रम में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, राजस्व एवं बाढ़ नियंत्रण राज्यमंत्री विजय कुमार कश्यप ने भी विचार रखे। ब्यूरो